ब्लैक एंड व्हाइट और रंगीन टेलीविजनों पर नकद मुआवजे के रूप में राहत का दिया जाना

1026. **श्री सन्तोष बागड़ोदिया :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने 14 इंच के ब्लैक एंड व्हाइट तथा रंगीन टेलीविजनों पर नकद मुआवजे के रूप में 15 प्रतिशत राहत देने की घोषणा की है ;

(ख) क्या सरकार यह सुविधा 20 इंच के टेलीविजनों पर भी देने का विचार रखती है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०आर०दासमुंशी) : (क) से (ग) सभी प्रकार के इलैक्ट्रोनिक उपकरणों तथा अनुषंगी सामान पर जिनमें शामिल हैं इलैक्ट्रोनिक संघटक और इलैक्ट्रोनिक यंत्र जिनमें सभी आकार के टी० वी० रिसीवर कवर होते हैं, के निर्यात पर 15 प्रतिशत की दर से नकद मुआवजा सहायता मंजूर की गई है।

राजस्थान में नाबार्ड द्वारा सिंचाई के पम्प सैटों के लिए वित्तीय सहायता

1027. **श्री सन्तोष बागड़ोदिया :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में सिंचाई के लिए प्रयोग में आने वाले उन पम्प सैटों की संख्या कितनी है जिनके लिए गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा आवश्यक धनराशि प्रदान की गई है ;

(ख) राज्य के प्रत्येक जिले को दिए गए ऐसे पम्प सैटों की संख्या कितनी है ;

(ग) क्या सरकार को इन पम्प सैटों के सही ढंग से कार्य न करने के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(घ) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) दोषपूर्ण पम्प सैट बेचने वालों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुवर्डो फेलेरियो) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

दालों के आयात पर शुल्क लगाया जाना

1028. **श्री सन्तोष बागड़ोदिया :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने दालों के आयात पर पिछले वर्ष लिये जाने वाले शुल्क को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 35 प्रतिशत कर दिया है जिससे दालों के मूल्य में तेजी से वृद्धि हुई है ;

(ख) क्या सरकार मूल्यों को कम करने के लिये दालों के आयात पर लगाये जाने वाले उक्त अतिरिक्त शुल्क को समाप्त करने का विचार रखती है ;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में दिल्ली अनाज व्यापारी संघ की ओर से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री अजीत पांजा) : (क) पिछले वर्ष अच्छी फसल होने की संभावनाओं को मद्देनजर रखते हुए

और किसानों को लाभकर मूल्य प्राप्त हो, इस तरह उनकी सहायता करने की बात को ध्यान में रखकर, 3 अक्तूबर, 1988 से दालों पर आयात शुल्क को मूल्यानुसार 10 प्रतिशत से बढ़ाकर मूल्यानुसार 35 प्रतिशत कर दिया गया था।

(ख) से (घ) दिल्ली आनाज व्यापारी संघ ने एक ज्ञापन दिया है जिसमें उसने दालों पर आयात शुल्क को हटाने के लिए अनुरोध किया है। दालों पर आयात शुल्क को कम करने के लिए सरकार पर्याप्त औचित्य नहीं देखती है।

भारत में पाकिस्तान की इन्टर सर्विसिज इन्टेलीजेंस एजेंसी की गतिविधियां

1029. डा० रत्नाकर पाण्डेय : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पाकिस्तानी समाचार पत्रों में प्रकाशित इस आशय के एक समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें यह कहा गया है कि पाकिस्तान की इन्टर सर्विसिज इन्टेलीजेंस एजेंसी भारत में सक्रिय रही थी और इस एजेंसी के लिये पाकिस्तानी सरकार द्वारा धनराशि मंजूर की गयी थी ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) और (ख) भारत में पाकिस्तान की "इन्टर सर्विसिज इन्टेलिजेंस" की गतिविधियों को स्पष्ट रूप से अभिस्वीकृत करने से संबंधित कोई प्रेस रिपोर्ट सरकार के ध्यान में नहीं आयी है। तथापि 18 जून, 1989 के पाकिस्तानी दैनिक "दी नेशन" में प्रकाशित एक लेख में आई. एस. आई. के घटे हुए स्तर पर टिप्पणी की गई है। इस लेख में कहा गया है कि भारत में प्रचालन कार्रवाईयां समाप्त कर दी गई हैं और इसे पैसा देना बंद कर दिया गया है। इससे यह भाव निकाला जा सकता है कि आई.एस.आई. भारत में सक्रिय थी और पाकिस्तान सरकार द्वारा इसे धनराशि मंजूर की जाती थी। सरकार देश की सुरक्षा के लिए उत्पन्न खतरे के बारे में भली भांति अवगत है।

Irregularities committed in Indore branches State Bank of Indore

1030. SHRI ASHOK NATH VERMA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) the number of branches of the State Bank of Indore operating at Indore and the number of cases regarding bungling/irregularities committed in these branches brought to light during the last three years and upto 30 June, 1989;

(b) the details of the amount involved in these cases; anl

(c) the number of officers/employees found guilty and the action taken in each case?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI EDUARDO FALEIRO): (a) to (c) Information is being collected and to the extent available, will be laid on the Table of the House.

Filling up of SC/ST vacancies in the office of the development Commissioner, Delhi Administration

1031. SHRI DHULESHWAR MEENA: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that according to the latest Government policy, all vacancies of SC and ST must be filled up within the stipulated time;

(b) if so, what are the reasons for which the candidates belonbing to the